गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)

संदर्भ: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने घोषणा की, कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीद में उल्लेखनीय 10 गुना वृद्धि हुई है।

- केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने पिछले तीन वर्षों में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से खरीद में उल्लेखनीय "10 गुना" वृद्धि पर प्रकाश डाला।
- प्लेटफ़ॉर्म ने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, दक्ष और लागत-प्रभावी बनाया है।
- GeM ने वित्त वर्ष 2022-23 में ₹2 लाख करोड़ का सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) दर्ज किया, जबकि इसकी स्थापना के बाद से इसका संचयी GMV ₹4.29 लाख करोड़ है।
- GeM पर लेनदेन की कुल संख्या 1.54 करोड़ से अधिक हो गई है।
- GeM 69,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठनों की खरीद आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- पोर्टल में 11,800 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और 280 से अधिक सेवा श्रेणियां हैं।
- GeM के परिणामस्वरूप सम्बंधित, प्लेटफ़ॉर्म पर न्यूनतम बचत 10% होने का अनुमान है, जो लगभग 40,000 करोड़ रूपए की सार्वजनिक बचत के बराबर है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय GeM प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स क्षमताओं के साथ एक अधिक उन्नत और आधुनिक प्रणाली विकसित करने की योजना है।
- वित्त वर्ष 22-23 में GeM खरीद प्रक्रिया में सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए GeM ने 'क्रेता-विक्रेता गौरा सम्मान समारोह 2023' का आयोजन किया।
- GeM में 63,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन और 62 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2016 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है।
- GeM सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और अन्य संगठनों के लिए सुलभ है।
- सिंगापुर के GeBIZ से पीछे रहकर GeM समान प्लेटफार्मों के बीच वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान रखता है।
- दुनिया भर में सबसे बड़ा खरीद मंच दक्षिण कोरिया का KONEPS है।
- GeM का लक्ष्य भारत में सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और लागत-प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

जीईएम 4.0

नई सुविधाएँ और संवर्द्धन:

- विक्रेताओं के लिए समय पर भुगतान।
- प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) के साथ उन्नत सर्च इंजन।
- समेकित आदेशों के लिए मांग एकत्रीकरण।
- क्रमबद्ध या लचीले वितरण विकल्प।
- लक्षित बोली के लिए पुन: डिज़ाइन किया गया बोली मॉड्यूल।
- एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों का एकीकरण।
- बेहतर शिकायत निवारण तंत्र।
- मूल्य भिन्नता के साथ सरलीकृत कैटलॉगिंग।

- बैंकों और ईआरपी के एकीकरण के साथ उन्नत भुगतान विकल्प।
- सूचित निर्णय लेने के लिए विक्रेता रेटिंग का परिचय।
- नई सेवाओं और श्रेणियों का समावेश।
- विक्रेताओं और खरीदारों के बीच सीधा संवाद।
- सीपीएसयू (केंद्रीय पीएसयू) के लिए समर्पित पेज।

'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24'

संदर्भ: चालू वित्तीय वर्ष में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 16 राज्यों में कुल 56,415 करोड़ रूपए के पूंजी निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

- भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाओं स्वीकृति प्रदान की है।
- जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य की हिस्सेदारी को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत राज्यों को धन उपलब्ध कराया गया है, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में परियोजनाओं में तेजी लाना है।
- राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24' की घोषणा की गई थी।
- इस योजना में निम्नलिखित भाग शामिल हैं:
  - ✓ भाग- I में केंद्रीय करों और शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर राज्यों के बीच 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन वितरित किया गया है।
  - ✓ भाग-II में राज्य सरकार के वाहनों को स्क्रैप करने, पुराने वाहनों पर देनदारियों की छूट, पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए कर रियायतें और स्वचालित वाहन परीक्षण सुविधाओं की स्थापना से संबंधित प्रोत्साहनों के लिए 3,000 करोड़ रुपये रुपये की राशी निर्धारित है।
  - ✓ भाग-III और भाग-IV शहरी नियोजन और शहरी वित्त में सुधारों के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसमें शहरी नियोजन सुधारों के लिए 15,000 करोड़ रुपये और शहरी स्थानीय निकायों की साख को प्रोत्साहित करने और वित्तीय सुधार के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशी निर्धारित है ।
  - ✓ भाग-V 2,000 करोड़ रुपये की निर्धारित राशि के साथ शहरी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों के भीतर पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवास स्टॉक बढ़ाने पर केंद्रित है।
  - ✓ भाग-VI का उद्देश्य 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ प्रत्येक राज्य में यूनिटी मॉल के निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और "मेक इन इंडिया" की अवधारणा को बढ़ावा देना है।
  - ✓ भाग-VII बच्चों और किशोरों के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे के साथ पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- राज्यों को पूंजी निवेश/व्यय के लिए वित्तीय सहायता की योजना पहली बार 2020-21 में COVID-19 महामारी के काल में शुरू की गई थी और इसकी प्रभावशीलता के लिए इसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

- पिछले वित्तीय वर्ष में '2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना के तहत 95,147.19 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी और राज्यों को 81,195.35 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय
परिभाषा	मौजूदा संपत्ति की आयाम बढ़ाने के लिए संपत्ति प्राप्ति के लिए किए गए व्यय, जिससे इसकी समय-सीमा में वृद्धि होती है	व्यापार की दैनिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए उपयोगिता के लिए किए गए खर्च।
कार्यकाल	लंबे समय तक।	छोटी अवधि तक।
मूल्य वृद्धि	मौजूदा संपत्ति की मूल्य वृद्धि करती है।	मौजूदा संपत्ति की मूल्य वृद्धि नहीं करती है।
भौतिक उपस्थिति	भौतिक उपस्थिति होती है।	भौतिक उपस्थिति नहीं होती है।
आवेदन की प्रकृति	गैर-आवृत्तिक।	आवृत्तिक।
पूंजीकरण की उपलब्धता	हाँ	नहीं
आय पर प्रभाव	व्यापार की आय को कम नहीं करता।	व्यापार की आय को कम करता है।
संभावित लाभ	व्यापार के लिए दीर्घकालिक लाभ।	व्यापार के लिए अल्पकालिक लाभ
दिखने का ढंग	बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखता है।	आय वक्तव्य में हमेशा दिखता है।

जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वित्तीय समझौते से मुख्य निष्कर्ष

संदर्भ: हाल ही में पेरिस में 'जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वित्तीय संधि' शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ है।

मुख्य परिणाम

पेरिस में 'जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वित्तीय समझौता' शिखर सम्मेलन के परिणाम:

- अतिरिक्त ऋण देने की क्षमता:
  - ✓ बहु-विकास बैंकों (एमडीबी) की ऋण देने की क्षमता 200 अरब डॉलर बढ़ जाएगी।
  - ✓ इस धनराशि का उपयोग जलवायु चुनौतियों से निपटने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने के लिए किया जाएगा।
- विश्व बैंक: ऋण भुगतान का निलंबन:
  - ✓ विश्व बैंक ने ऋण सौदों के लिए आपदा खंड शामिल करने की घोषणा की है ।
  - ✓ वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए चरम मौसम की घटनाओं की स्थिति में ऋण भुगतान निलंबित कर दिया जाएगा।
- आईएमएफ उपाय:
  - ✓ आईएमएफ द्वारा प्रदान किए गए एक अंतरराष्ट्रीय रिजर्व, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के माध्यम से गरीब देशों को 100 अरब डॉलर प्रदान किए जाएंगे।

- ✓ विकासशील देशों के लिए उपलब्ध रियायती वित्त की मात्रा का विस्तार करते हुए अमीर देशों से गरीब देशों में एसडीआर का पुनर्चक्रण करने का प्रस्ताव।

➢ सेनेगल के लिए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (जेईटीपी):
- ✓ विशेष रूप से सेनेगल के लिए नए 2.5 बिलियन यूरो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप (जेईटीपी) सौदे की घोषणा की गई है
- ✓ इस सौदे का लक्ष्य सेनेगल के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना है।

➢ प्रदूषणकारी कर:
- ✓ प्रदूषक करों पर कार्यवाही तीव्र की गई है।
- ✓ शिखर सम्मेलन ने पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक प्रथाओं को हतोत्साहित करने के साधन के रूप में प्रदूषण करों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया।

➢ ऋण पर समीक्षा:
- ✓ ऋण, प्रकृति और जलवायु पर वैश्विक विशेषज्ञ समीक्षा का प्रस्ताव।
- ✓ समीक्षा का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों की क्षमता पर ऋण के प्रभाव का आकलन करना है।

➢ यूरोपीय संघ के उपाय:
- ✓ यूरोपीय संघ ने 'पेरिस एलाइन्ड कार्बन मार्केट्स' पर कार्रवाई के आह्वान का अनावरण किया।
- ✓ जलवायु संरेखण के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के साथ वैश्विक उत्सर्जन के कम से कम 60% को कवर करने का लक्ष्य है।

➢ 100 अरब डॉलर का जलवायु वित्त लक्ष्य:
- ✓ वर्तमान वर्ष (2023) में लंबे समय से प्रतीक्षित $100 बिलियन के जलवायु वित्त लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता।
- ✓ यह धनराशि जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों के प्रयासों का समर्थन करेगी।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

जीआई टैग

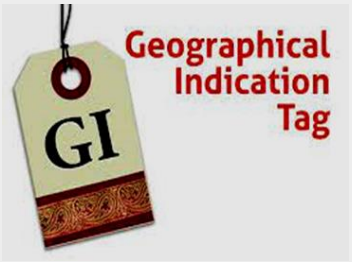

सन्दर्भ:

हाल ही में चेन्नई में अवस्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के सात विभिन्न उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दी है ।

उत्तर प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पाद:

अमरोहा के ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत घरेलू सजावट सामग्री, बाराबंकी हस्तनिर्मित उत्पाद और कालपी हस्तनिर्मित कागज ।

भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री:

भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री एक सरकारी निकाय है जो किसी देश में भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

जीआई टैग क्या है?

जीआई टैग बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप है जो किसी उत्पाद को एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पाद के रूप में पहचान देता है।

ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना:

जीआई टैग पारंपरिक प्रथाओं में लगे ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को मान्यता और

	मूल्य प्रदान करते हैं, उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण को प्रोत्साहित करते हैं । **राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता:** जीआई टैग राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत दिए जाते हैं । भारत में, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम जीआई टैग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जीआई संरक्षण बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते के तहत कवर किया गया है।
कुनो राष्ट्रीय उद्यान 	**सन्दर्भ:** हाल ही में, भारत के मध्य प्रदेश में अवस्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के बीच झड़प के दौरान, राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित चीतों में से एक घायल हो गया। **कूनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP):** कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह कूनो नदी के किनारे स्थित है, जो चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस पार्क को वर्ष 1981 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में बनाया गया था जबकि इसे वर्ष 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। **जीव-जंतु:** यह पार्क विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर है, जिनमें भारतीय भेड़िये, सियार, तेंदुए, लंगूर प्राइमेट, चिंकारा, चित्तीदार हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चार सींग वाले चिंकारे, काले हिरण, भारतीय खरगोश, दक्षिणी घास के मैदान के ग्रे लंगूर, तेंदुए, सुस्त भालू, चित्तीदार लकड़बग्घे, भूरे भेड़िये, सुनहरे सियार, भारतीय लोमड़ी और रैटल आदि शामिल हैं। इस पार्क में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ (टी-38) की वापसी भी देखी गई है। **चीता पुनरुत्पादन:** भारत में चीतों के पुनरुत्पादन के लिए संभावित आवास के रूप में कुनो राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया था। चीतों को फिर से लाने की योजना पर वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी, लेकिन वर्ष 2020 में इसने प्रायोगिक आधार पर अफ्रीकी चीतों को लाने की अनुमति दे दी। जनवरी 2022 में, भारत सरकार ने चीतों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया। वर्तमान में, नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को पार्क में स्थानांतरित किया गया है, और अगले पांच वर्षों में लगभग 50 चीतों को लाने की योजना है।
अनुसंधान चिंतन शिविर	**सन्दर्भ:** हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने नई दिल्ली में 'अनुसंधान चिंतन शिविर' का आयोजन किया। **उद्देश्य:**

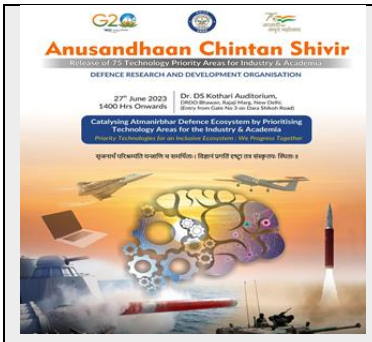

'अनुसंधान चिंतन शिविर' का प्राथमिक उद्देश्य उद्योग और शिक्षा जगत के भीतर रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है ।

प्रौद्योगिकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का विमोचन:

इस अवसर पर डीआरडीओ की ओर से 75 प्रौद्योगिकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सूची जारी की गई ।

इन क्षेत्रों को आगे 403 तकनीकी श्रेणियों में विभाजित किया गया और 1,295 वर्तमान और भविष्य के प्रौद्योगिकी विकास कार्यों तक विस्तारित किया गया ।

डीआरडीओ प्रौद्योगिकी दूरदर्शिता 2023:

इस कार्यक्रम में डीआरडीओ प्रौद्योगिकी दूरदर्शिता 2023 दस्तावेज़ का भी अनावरण किया गया।

उन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की भी पहचान की गई जिन पर डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाएँ वर्तमान में काम कर रही हैं।

डीआरडीओ की भूमिका:

डीआरडीओ, प्रयोगशालाओं और केंद्रों के अपने नेटवर्क के साथ, विभिन्न विषयों में रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में सक्रिय रूप से संलग्न है।

इसकी मुख्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना, साथ ही उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है ।

खर्ची पूजा

सन्दर्भ:

खर्ची पूजा एक स्थानीय त्योहार है, जिसे '14 देवताओं का त्योहार' भी कहा जाता है, वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में इसे मनाया जा रहा है।

खर्ची पूजा:

यह त्यौहार जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान विशेष रूप से अमावस्या के आठवें दिन मनाया जाता है।

इसका नाम, खारची, त्रिपुरी शब्द "खर" या "खरता" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "ची" या "सी", अर्थात सफाई, जो पापों/बुराई की सफाई का प्रतीक है।

खर्ची पूजा हिंदू कैलेंडर के अनुसार 'आषाढ़' महीने के दौरान 'शुक्ल अष्टमी' के दिन आयोजित की जाती है।

पूजा एवं अनुष्ठान:

शाही पुजारी, जिन्हें 'चंटाई' के नाम से जाना जाता है, खर्ची पूजा के दौरान अनुष्ठान का संचालन करते हैं।

पूजा का प्राथमिक उद्देश्य चौदह देवताओं की पूजा है, जिन्हें त्रिपुरा में विभिन्न दिव्य संस्थाओं के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है ।

पूजा पुराने अगरतला में चतुर्दश देवता मंदिर परिसर में होती है, जहां सभी चौदह देवता प्रतिष्ठित हैं।

ताइवान जलडमरूमध्य

सन्दर्भ:

भारत ताइवान जलडमरूमध्य के रणनीतिक महत्व को पहचान कर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में शांति बनाए रखने के लिए भारत-प्रशांत देशों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता रखता है।

भौगोलिक स्थिति:

ताइवान जलडमरूमध्य ताइवान द्वीप और महाद्वीपीय एशिया को अलग करने वाली 180 किलोमीटर चौड़ी जलडमरूमध्य है। यह दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है और उत्तर में पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है।

महत्व:

ताइवान जलडमरूमध्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में शिपिंग और व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है।

यह जलसंधि चीन और ताइवान के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव और विवाद के कारण भी महत्वपूर्ण है।

भारत की स्थिति:

भारत अपनी समुद्री सुरक्षा चिंताओं और भारत-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक संबंधों के कारण ताइवान जलडमरूमध्य की स्थिरता में रुचि रखता है।

भारत ने एक चीन नीति बनाए रखी है, लेकिन व्यापार, निवेश और लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में ताइवान के साथ सहयोग बढ़ाने की भी मांग की है।

भारत-प्रशांत सहयोग:

ताइवान जलडमरूमध्य मुद्दा भारत-प्रशांत राज्यों के लिए सहयोग करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने का अवसर प्रस्तुत करता है।

भारत, इंडो-पैसिफिक में एक प्रमुख भागीदार के रूप में, ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव को हल करने और शांति बनाए रखने के लिए बातचीत और राजनयिक प्रयासों को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकता है।